>

Title: Need to provide full benefit of educational loan by State Bank of India to students of Indian Maritime University, Kolkata, West Bengal.

श्री हरी माझी (गया): भारत सरकार ने ऐसे मेधावी छात्र छात्रायें जो गरीब परिवार से आते हैं तथा दूसरे राज्य में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अपनी शिखा पूर्ण करने में किसी तरह की आर्थिक कमी न हो इसके लिए रियायती दर पर सरकार शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है जिससे हर वर्ष हजारों गरीब एवं मेधावी छात्रों को देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई पूरी कर अपना भविष्य संवारने का मौका मिलता है। नःसंदेह सरकार द्वारा लिया गया निर्णय सराहनीय है। परंतु कुछ बैंकों द्वारा अनावश्यक रूप से ऋण लेने की प्रक्रिया को जटिल बनाकर लाभार्थियों की संख्या में कमी की जाती है।

देश के अग्रणी शिक्षण संस्थानों में एक इंडियन मेरीटाईम विश्वविद्यालय कलकत्ता कैम्पस विद्यार्थियों के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। वहाँ के भारतीय स्टेट बैंक के अलीपुर शाखा द्वारा उक्त संस्थान के विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 9 लाख रूपये ऋण उपलब्ध कराया जाता था किन्तु वर्तमान वर्ष में यह राशि घटाकर 7 लाख रूपये कर दी गई है। आज जबकि महंगाई बढ़ रही है ऐसी स्थिति में ऋण को घटाना समझ से परे है। पहले ऋण उपलब्ध कराने का तरीका सहज था लेकिन इस वर्ष तरीका जटिल होता जा रहा है। अभिभावकों से अपने स्थायी पते पर निकटतम बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र माँगा जा रहा है जबकि बैंक पहले यह काम स्वयं कराती थी।